

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 259 बेमेतरा, शनिवार 16 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

पहला कॉलम

अंडमान और निकोबार में 16 मई को पहुंचेगा मानसून

नईदिल्ली। गर्मी से जूझ रहे लोगों को इस बार मानसून की बारिश थोड़ी जल्दी राहत दे सकती है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून 16 मई को दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगर 16 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश शुरू होती है तो मानसून 25 से 30 मई तक केरलम में प्रवेश कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अंडमान और निकोबार मानसून पहुंचने पर अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में बंटता है। ऐसे में अरब सागर शाखा अगर 30 मई तक केरलम में बारिश शुरू करता है तो यह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समय से पहले पहुंचेगा। हालांकि, दक्षिण के राज्यों में मानसून पूर्व बारिश शुरू हो गई है। इन इलाकों में 17 मई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

ममता बनर्जी वकील की पोशाक में कलकता हाई कोर्ट पहुंचीं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी गुरुवार को वकील की सफेद-काली पोशाक में कलकता हाई कोर्ट पहुंची हैं। ममता कोर्ट में विधानसभा चुनावों में टीएमसी की करारी हार के बाद शुरू हुए हिंसा के आरोपों से संबंधित एक मामले की सुनवाई पर बहस करेंगी। यह याचिका वरिष्ठ टीएमसी नेता और अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के बेटे शिरासन्ना बनर्जी ने दायर की है, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से संबंधित है। ममता के कोर्ट पहुंचने पर टीएमसी ने एक्स पर एक बयान जारी किया है। पार्टी ने लिखा कि ममता बनर्जी स्वयं हाई कोर्ट पहुंचीं, ताकि भाजपा द्वारा बंगाल में चुनाव के बाद फैलाई गई व्यापक हिंसा से जुड़े मामले में बहस कर सकें। पार्टी ने लिखा कि एक बार फिर, ममता ने साबित कर दिया है कि कौन सी बात उन्हें सचमुच सबसे अलग बनाती है।

संजय कपूर संपति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ली चुटकी- इसके सामने महाभारत भी छोटी लगेगी

नईदिल्ली। दिग्गज कारोबारी और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के परिवार में चल रहा संपति का झगड़ा अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। 30,000 करोड़ रुपये की भारी-भरकम जायदाद को लेकर अपनों के बीच मचे इस घमासान को देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। मामले की गंभीरता और परिवार की आपसी कलह देखते हुए कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये विवाद इतना बड़ा और पेचीदा है कि इसके सामने महाभारत भी छोटी लगने लगेगी। ये टिप्पणी जज जेबी पारदीवाला की पीठ ने की। अदालत संजय कपूर की 80 वर्षीय मां रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

दुनिया में ईंधन की कीमतों में आग

जनता को झटका-पेट्रोल 3.14 और डीजल 3.11 रुपए महंगा..

नई दिल्ली/ एजेंसी

जिस बात का डर था, आखिरकार वही हुआ। देश की जनता को 15 मई की सुबह-सुबह तगड़ा झटका लगा है। देश में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। पेट्रो कंपनियों ने पेट्रोल 3.14 रुपए और डीजल 3.11 रुपए दाम बढ़ा दिए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के नए दाम शुक्रवार (15 मई 2026) से लागू हो गए हैं। जहां दिल्ली में पेट्रोल 3 रुपये महंगा होकर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया है, तो कोलकाता में ये 108.74 रुपये (3.29 रुपये महंगा) हो गया है। जबकि मुंबई में 106.68 रुपये (3.14 रुपए महंगा) और चेन्नई में 103.67 रुपये (2.83 रुपए) प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। डीजल की कीमतों की बात करें तो उसमें भी पेट्रोल की तरह दिल्ली में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में जिस डीजल के दाम पहले 87.67 रुपये प्रति लीटर थे, वह अब बढ़कर 90.67 रुपये



प्रति लीटर हो गया है। इसी तरह कोलकाता में डीजल की कीमतें 3.11 रुपये बढ़कर 95.13 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं। मुंबई में डीजल 3.11 रुपये प्रति लीटर बढ़कर अब 93.14 रुपये प्रति लीटर हो गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में डीजल 2.86 रुपये प्रति लीटर महंगा होकर 95.25 रुपये में मिल रहा है। मिडिल-ईस्ट जंग की शुरुआत के बाद से ये पहली बार है, जब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की संभावना काफ़ी समय पहले से बनी हुई थी। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के कारण बढ़ाया नहीं गया था। अब चुनाव खत्म

होने के 10 दिन के अंदर ही भारी बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से प्यूल बचाने की अपील की थी। उन्होंने वर्क प्रॅम करने और निजी वाहनों के कम इस्तेमाल पर जोर दिया था। तभी से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थीं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में ?2 प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। हालांकि ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ़होर्मुज बंद होने से देश में तेल और गैस की सप्लाई लगभग ठप हो गया है।

3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में....राहुल गांधी

खाड़ी युद्ध का हवाला देकर पेट्रो कंपनियों ने आज सुबह-सुबह पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भयंकर गुस्से में हैं। पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा साधते हुए कहा कि 3 का झटका आ चुका है। बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने पर लोकसभा नेता प्रतियक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- गलती मोदी सरकार की. कीमत जनता चुकाएगी। ?3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। बता दें कि अमेरिका- ईरान युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ़होर्मुज बंद है। इससे कारण खाड़ी देशों से तेल और गैस का सप्लाई ठप है। तेल और गैस की सप्लाई ठप होने के कारण पूरा विश्व तेल और गैस की कमी से जूझ रहा है। वरुड ओयल और तेल की कीमतों में बेतहासा बढ़ोतरी का असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा है। पेट्रो पंक्तियों ने आज (15 मई) सुबह पेट्रोल की कीमत में 3.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3.11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए हैं।



अवमानना नोटिस थमाकर छोड़ा केस

शराब घोटाला केस से क्यों अलग हुई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ?

नई दिल्ली/ एजेंसी

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब घोटाला मामले से खुद को अलग कर लिया है। गुरुवार को केस से हटने से पहले उन्होंने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल समेत आप के नेताओं को अवमानना का नोटिस थमाकर कार्रवाई शुरू की और शराब घोटाला केस से खुद को अलग किया। उनके इस फैसले के बाद अब किसी अन्य जज को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। बता दें, कि सीबीआई ने शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपी बताया है। हालांकि, राजउ एक्वेन्यू कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने खुद को इस केस से अलग क्यों किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल, सीबीआई ने राजउ एक्वेन्यू कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी दौरान यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता के सामने आया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस केस से हटने की अपील की



केजरीवाल-सिसोदिया के खिलाफ नोटिस

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस मामले में कार्रवाई न करने से अराजकता फैल जाएगी। इसके अलावा, मनीष सिसोदिया और दुर्गाश पाठक के खिलाफ भी आपराधिक अवमानना के नोटिस जारी किए गए। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आबकारी नीति मामले की सुनवाई अब से कोई अन्य न्यायाधीश करेंगे। हालांकि, न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले से खुद को इसलिए अलग नहीं कर रही हैं।

थी, लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता ने इस अपील को अस्वीकार कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने जज के फैसले की धोती। इसी दौरान यह मामला जस्टिस स्वर्णकांता के सामने आया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस केस से हटने की अपील की

कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच भारत का पहला समुद्री विमान, अगाती हवाई अड्डे पर सफल ट्रायल

एर्नाकुलम। केरलम के कोच्चि से खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप तक भारत के पहले समुद्री विमान (सीप्लेन) का चलना जल्द ही साकार होने वाला है। दोनों इलाकों में समुद्री विमान का ट्रायल सफल हो गया है। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लक्षद्वीप भारत की पहली सीप्लेन कनेक्टिविटी का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्राधिकरण ने कहा कि अगाती वॉटरड्रोम पर सीप्लेन का सफल ट्रायल लैंडिंग हुआ, जो एक बड़ा मील का पत्थर है।



तमिलनाडु के विधायकों ने नई दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की.

यूएई पर हमला मंजूर नहीं.....

पीएम मोदी बोले-भारत किसी भी वक्त मदद के लिए तैयार...

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च-अप्रैल में संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान द्वारा किए हमलों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यूएई पर हुए हमलों की हम घोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। पीएम मोदी अपने पांच देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी आज से पांच देशों की विदेश यात्रा पर हैं। इस कड़ी में वो सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ़ऑनर भी दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की उपस्थिति में दोनों देशों ने एमओयू का आदान-प्रदान किया, जिसमें

रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भी शामिल है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय वार्ता में पीएम मोदी ने कहा कि आज जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानी आई, आपने उन पीड़ित परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की, इसके लिए भी मैं



आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी ने कहा कि यूएई पर हुए मध्य-पूर्व में मौजूदा हालातों पर हमलों की हम घोर निंदा करते हैं।

री-एग्जाम की नहीं देनी होगी फीस

अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड होगी नीट परीक्षा- मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के री-एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इसी दौरान कंप्यूटर बेस्ड नीट एग्जाम का भी ऐलान किया। अब 22 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। एनटीए अब 21 जून को नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित कर रही है। इस विषय में शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने जानकारी दी कि 14 जून तक सभी छात्रों को एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। नीट परीक्षा के दिन छात्रों के आवागमन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। दोबारा परीक्षा की कोई फीस नहीं लेंगे। सभी छात्रों को एक हफ्ते पहले परीक्षा सेंटर चुनने का विकल्प दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा, परीक्षा से जुड़ी औपचारिकताओं, जैसे कि ओएमआर शीट पर शुरू और आखिर में हस्ताक्षर करने के बारे में एक और बात उठाई गई थी। इससे छात्रों को मिलने वाला मुख्य समय



कम हो रहा था। परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होने को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने इसे 15 मिनट और बढ़ाने का फैसला किया है। अब सभी छात्रों को परीक्षा के दौरान 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पेपर लोक मामले को लेकर कहा कि इस बार पेपर लोक माफिया को सजा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पेपर लोक को डॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ओएमआर शीट पर शुरू और डॉलरेंस नीति है और यह परीक्षा माफिया के खिलाफ एक लंबी लड़ाई है।

बरसो रे मेघा बरसो!

रायपुर,महासमुंद समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश,आंधी-बरिश का असर,पेड़ धराशाई.....

रायपुर। राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से बादल गरजने के साथ बारिश हो रही है. टर्फ और साइक्लोनिक सक्शुलेशन के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला है. रायपुर में काले बादल छा चुके हैं और मानसून जैसी बारिश हो रही है. इसके अलावा बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी और रायगढ़ में तेज हवाओं और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. रायपुर में सुबह से मौसम बिगड़ गया. लगभग 8 बजे के बाद आसमान में काले बादल छाए और बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. बादल गरजने के साथ बारिश होने लगी. ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. बलौदा बाजार में मौसम ने करवट ली. बीती देर रात आए आंधी तूफान में जिला मुख्यालय में कई जगह बड़े पेड़ बीच सड़क पर धराशाई हो गए. इससे आवागमन बाधित हो गया. आज सुबह दुकान दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का



सामना करना पड़ा. वहीं नगरपालिका की एक टीम रास्ता क्लियर करने में लगी हुई है. वहीं

बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई है. महासमुंद जिले में देर रात से शुरू हुई आंधी-तूफान के बाद बिजली व्यवस्था चरमरा गई. वहीं सुबह से गरज-चमक के साथ पिथोरा में तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. बारिश के चलते गांवों की गलियां पानी-पानी हो गई. इश्वर रायगढ़ में भी रायपुर के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. सुबह से बादल छाए रहने के बाद गरज-चमक के साथ बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया.

पकड़ा गया नीट पेपर लोक का मास्टरमाइंड!

एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल था ये प्रोफेसर

नई दिल्ली/ एजेंसी

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के पेपर लोक मामले में सीबीआई को एक बहुत बड़ी और निर्णायक सफलता हाथ लगी है। सीबीआई ने इस पूरे घोटाले के मुख्य सरना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पी.वी. कुलकर्णी के रूप में हुई है। सीबीआई की जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने एनटीए की सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।



गिरफ्तार आरोपी पी.वी. कुलकर्णी खुद एनटीएकी परीक्षा प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा था, जिसके कारण उसकी पहुंच सीधे गोपनीय प्रश्नपत्रों तक हो गई थी।

यूएई को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, ये बहुत ही सराहनीय हैं। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है।

भारत ने मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी है। होर्मुज स्ट्रेट को मुक्त, खुला और सुरक्षित रखना हमारी बड़ी प्राथमिकता है। इस मामले में, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। भारत हर स्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। भारत जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है।

समस्याओं का सरल, पारदर्शी एवं समय-समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि -संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलता है और सरकार गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुनने एवं उनका निराकरण करना का कार्य कर रही है।

विभिन्न विभागों के आवेदनों पर मुनवाइ-शिविर में कृषि, राजस्व, पंचायत स्वस्थ, महिला एवं बाल विकास, खेती सामाजिक कल्याण एवं अन्य विभागों से संबंधित आवेदनों पर चर्चा की गई। कई मामलों का पत्र पर ही निराकरण किया गया, जबकि अन्य आवेदनों को संबंधित विभागों को समय-सीमा कार्रवाई हेतु सौंपा गया।

कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि सरपंचाण, सचिव, अधिकारी-कर्मचारी एवं संस्था में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर सफल आयोजन से ग्रामीणों में उत्साह एवं सकारात्मक वातावरण देखने को मिला।

संपादकीय

आखिर क्या वजह है कि विद्यार्थियों के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाने की नौबत आई है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी आंदोलन या प्रदर्शन को लेकर सरकार का यह रुख सामने आया है। बिहार के पटना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान राज्य की पुलिस का जैसा खेया सामने आया है, उसे आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत

किसी मसले पर सरकार से विचार की मांग के स्वर का दमन करने की तरह देखा जा सकता है।सवाल है कि अगर नागरिकों के सामने अपनी किसी मांग के लिए आंदोलन या प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है, तो संवाद के जरिए उनकी समस्या का समाधान करने या कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी या उन्हें चुन कराने के लिए सीधे लाठी-

डेके को सहारा लिया जाएगा? हेरानो की बात है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रक्रिया में लगातार देरी और टालमटोल से परेशान विद्यार्थियों ने जब पटना में विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो उनकी मांगों पर विचार करने के बजाय उन पर लाठी चार्ज किया गया और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अगर उन्हें रोकेना भी था, तो पानी की बोख़र या कोई अन्य उपाय करने के बजाय

बहराम से उन पर लाठीयां चलाता हा अकेला उपाय क्यों माना गया? राज्य की पुलिस के इस रवैये को क्या किसी भी तरह से प्रदर्शनकारियों के प्रति एक लोकतांत्रिक शासन की प्रतिनिधिता कहा जा सकता है? अगर नागरिकों के किसी हिस्से को सरकार से अपने अधिकार या अन्य मांग करने से इस तरह रोका जाएगा, तो उसमें नागरिक अधिकारों की क्या जाह रह जाएगी? आखिर क्या वजह

हे कि विद्यार्थियों के सामने शिक्षक भर्ती को पहला गुमराह करने का आरोप लगाने की नौबत आई है? यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी अदालत या प्रदर्शन को लेकर सरकार का यह रुख सामने आया है। इससे पहले भी कई बार विद्यार्थियों और अन्य नागरिक समूहों ने अलग-अलग मुद्दे पर प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी मांगों पर विचार या बातचीत करने के

बजाय उन्हें चुप करने और भागने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया गया। अफसोसनाक यह है कि बिहार में जो पार्टियाँ फिलहाल सत्ता में हैं, उन्होंने एक समय जनता की उपेक्षा किए जाने को ही मुद्दा बनाया था।

हकीकत यह है कि आंदोलनों या प्रदर्शन के प्रति पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार का जो रवैया है, उससे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए जान सिमट रही है।

रोगियों की मुस्कान और उम्मीद का दूसरा नाम हैं नर्स

सचमुच नर्स अस्पतालों की आत्मा होती हैं। चिकित्सक जहां रोग की पहचान और उपचार का मार्ग तय करता है, वहीं नर्स अपने स्पर्श, सेवा, सहानुभूति और निरंतर देखभाल से रोगी को जीने की शक्ति देती है। रोगी जब दर्द, भय, चिंता और असहायता से घिरा होता है, तब नर्स ही उसके चेहरे पर विश्वास की मुस्कान बनकर सामने आती है। वह केवल इंजेक्शन लगाने, दवाइयां देने या रिपोर्ट संभालने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह रोगी के मनोबल की संरक्षक होती है। वह अपने व्यवहार, शब्दों और संवेदनाओं से रोगी को यह विश्वास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। यही कारण है कि दुनिया भर में नर्सों को धरती के फरिश्ते कहा जाता है। मानवीय सेवा का सबसे जीवंत और प्रभावशाली स्वरूप यदि कहीं दिखाई देता है तो वह नर्सिंग सेवा में दिखाई देता है। एक नर्स रोगी की पीड़ा को केवल देखती नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करती है। वह रात-रात भर जागकर मरीजों की देखभाल करती है, उनके दर्द की भाषा समझती है, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है और कई बार अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी खुशियों की कीमत पर भी रोगियों की सेवा करती है।

(ललित गर्ग)

सचमुच नरसं अस्पतालों की आत्मा होती है। चिकित्सक जहाँ रोग की पहचान और उपचार का मार्ग तय करते हैं, वहीं नर्स अपने संरक्ष, सेवा, सहानुभूति और निरंतर देखभाल से रोगी को जीने की शक्ति देती है। रोगी जब दर्द, भय, चिंता और असह्यता से घिरा होता है, तब नर्स ही उसके चेहरे पर विश्वास की मुस्कान बनकर सामने आती है।

हर वर्ष 12 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाती है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग सेवा की जननी मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस उन अनगिनत संवेदनशील हाथों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जो दिन-रात रोगी के दर्द को कम करने, उन्हें जीवन का भरपूर आश और मृत्यु से संघर्ष कर रहे व्यक्ति के भीतर आशा का दीप जलाने का कार्य करते हैं। दुनिया में नर्सों की सेवा सार्वत्रिक महत्वपूर्ण है, हर दिन, नर्स शांत शक्ति, स्थिर हाथों और करुणा से भरे दिलों के साथ अस्पतालों, क्लीनिकों और विभिन्न सामुदायिक स्थानों पर कदम रखते हुए रोगियों के लिये देवदूत बनती हैं। नर्स भवना का रूप होती है, वे ही ईशान के जन्म की पहली साक्षी बनती हैं और उनमें करुणा का बीज बोती हैं। एक रोगी को स्वस्थ करने के वे अपना सब कुछ देती हैं। रोगी की सेवा करते हुए वे अपना परिवारिक सुख, करियर, जीवन और वर्तमान सबकुछ झोके देती हैं। वर्ष 2026 की थीम हमारी नर्स, हमारा भविष्य- सशक्त नर्स जीवन बनती है। पूरी दुनिया को यह संदेश देती है कि यदि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो नर्सों को सम्मान, सुरक्षा, सम्मान और सशक्त वातावरण देना होगा।

यह दिवस 1965 से इंटरनेशनल कार्डिसल ऑफ नर्सिंग द्वारा शुरू हुआ है, बहुत से लोग इस दिन का उपयोग अपने देश एवं दुनिया में नर्सों द्वारा किए गए अद्भुत सेवा कार्यों का सम्मान करने के लिए करते हैं।

सचमुच नरसं अस्पतालों की आत्मा होती है।
कितित्सक जहाँ रोग को पहचान और उपचार का मार्ग तय
करते हैं, वहीं नरसं अपने व्यर्थ, सेना, सहानुभूति और
निरंतर देखभाल से रोगी को जीने की शक्ति देते हैं। रोगी जब
दर, भय, चिंता और असह्यता से घिरा होता है, तब नरसं ही
उसके चहेत पर विश्वास की मुस्कान बनकर सामने आती है।
वह केवल इंसोवर्न लगाने, दवाइयों या रिपोर्ट संभालने
तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह रोगी के मनोबल की
समझ होती है, वह अपने व्यवहार, शब्दों और संवेदनाओं से
रोगी को यह विश्वास दिलाती है कि वह अकेला नहीं है।
यही कारण है कि दुनिया भर में नर्सों को धरती के फरिश्ते
कहा जाता है। मानवीय सेवा का सबसे जीवंत और
प्रभावशाली स्वरूप यह कहें दिव्यदा देते हैं तो वह नर्सों
नर्स में दिखाई देता है। एक नर्स रोगी की पीड़ा को केवल
देखती नहीं, बल्कि उस महसूस भी करती है। वह रात-रात

पर जागकर मरीजों को देखभाल करती है, उनके दर्द को भाषा समझती है, उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है और कोई भार अपने पर पतवार, अपने स्वास्थ्य और अपनी खुशियों को किमत पर भी गेयों की सेवा करती है। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय पूरी दुनिया ने देखा कि जब लोग अपने ही परिजनों से दूरी बना रहे थे, तब नर्स संक्रमित मरीजों के सबसे निकट खड़ी थीं। उन्होंने मृत्यु के भय को पीछे छोड़कर जीवन की रक्षा का संकल्प निभाया। उस दौर ने यह सिद्ध कर दिया कि नर्स के कल्याण

लेकिन वे रोगी की आंखों में छिपे भय को नहीं पढ़ सकती। तकनीक इलाज का माध्यम बन सकती है, लेकिन वह स्वस्थ बनकर रहना नहीं कर पाती। स्वस्थ बनना एक कला है। कला बनाना करण का विकल्प नहीं बन सकती। नर्सों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी संवेदनशीलता है, जो उन्हें अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाओं से अलग पहचान देती है। इसी कारण आज भी नर्सों दुनिया का सबसे अधिक अपेक्षित और सम्मानित स्वास्थ्य पेशा माना जाता है।

विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रशिक्षित नर्सों की कमी है। विकसित

बनाना होगा जहाँ नरें सम्मान और आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सकें। यदि नरें स्वयं तनाव, असुरक्षा और उपेक्षा से घिरी रहेंगी, तो स्वास्थ्य सेवाओं की मानवीय गुणवत्ता प्रभावित होगी। इसलिए नरों का कल्याण केवल उनके व्यक्तिगत प्रश्न नहीं, बल्कि पूरी मानवता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है।

अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को 2026 की थीम भी इस
सच को आगे बढ़ाती है कि सशक्त नर्सों ने जीवन बचाती हैं।
जब नर्सों को प्रशिक्षण, संसाधन, निर्माण लेने का अधिकार
और सामाजिक सम्मान मिलेगा, तभी वे अपनी पूरी क्षमता
के साथ समाज को स्वस्थ बना सकेंगी। यह दिवस हमें
केवल नर्सों का सम्मान करने की प्रेरणा नहीं देता, बल्कि यह
हमें यह दिलाता है कि नर्सों के बिना कोई भी स्वास्थ्य
व्यवस्था पूर्ण नहीं हो सकती। अस्पतालों की वास्तविकता
धड़कन में नहीं है। रोगियों की आंखों में लौटती चमक
परिवारों के चेहरे पर आती राहत और स्वस्थ जीवन की ओर
लौटते कदमों में नर्सों की निःस्वार्थ सेवा का मौन योगदान
छिपा होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज
नर्सों को केवल एक कर्मचारी के रूप में न देखे, बल्कि उच्च
मानवता के संवेदनशील रक्षकों के रूप में पहचाने। बच्चे
के जन्म से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक नर्सों का
महत्वपूर्ण क्षण में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। वे दर्द को हल
करती हैं, टूटे मन को संभालती हैं और निराशा में उम्मीद का
प्रकाश जगाती हैं। सच तो यह है कि नर्सों केवल शरीर का
उपचार नहीं करती, वे मनुष्य के भीतर जीने की इच्छा को भी
जीवित रखती हैं।

आम दिने हो या महामारियों के खिलाफ जंग, ये न बिना किसी डर के महज और उससाह से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि यह उनका काम है और उसने कति उन्हें पेस मिलते हैं बल्कि इसलिए कि वह सब पहले दूसरों के स्वस्थ होते और उनकी जान को फिक्र करते हैं। स्वास्थ के क्षेत्र में मां के स्वस्थ में खेदपूर्व और फिक्र का साथ हर किसी की देखभाल और परवाह करने के अर्थव्यवस्था न ही नई कहा जाता है। वे अस्पताल की रीड होती है। ऐसे मानवीय सेवा की अद्भुत फरिश्तों के कल्याण एवं प्रोत्साहन को का चिन्ता अपेक्षित है। उससे निश्चित है नर्सों की सेवा अधिक सक्षम, प्रभावी एवं मानवीय होकर सामने आयेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नवीय संकल्प अपेक्षित है कि हम नर्सों की सेवाओं को अधिक सम्मान, सुखा और सहयोग प्रदान करें। उनके कल्याण, प्रोत्साहन और सशक्तिकरण का व्यापक चिन्तन है। जब नर्सों का जीवन अधिक सुरक्षित, संतुलित और सम्मानपूर्ण होगा, तब उनसे सेवाएं और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और मानवीय बने सकेंगी। यही हम दिवस का वास्तविक उद्देश्य और मानवता के प्रति हमारी सच्ची संवेदनशीलता होगी। लोखक, पत्रकार, संपर्ककर्ता है। (सं लोख में लोखक के अपने विचार हैं।)



स्वास्थ्यकर्मी नहीं, बल्कि मानवता की सबसे मजबूत प्रहरी हैं।

नरिंगम सेवो केवल पेशा नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और
हृदय की साधना है। एक नर्स उस समय भी मुस्कुराती रहती
है जब वह स्वस्थ मानसिक और शारीरिक थकान से गुजर रही
होती है। वह रोगियों के बीच आशा का वातावरण बनाती है।
कई बार ऐसे मरीज, जो मानसिक रूप से टूट चुके होते हैं,
नर्सों की आत्मीयता और प्रेरणा से पुनः जीवन के प्रति
सकारात्मक हो जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान में दवाइयों की
अपनी भूमिका है, लेकिन संवेदनशील देखभाल और
मानसिक संबल रोगी के उपचार को अधिक प्रभावी बनाते
हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि नर्सों का संपर्क भी एक
औषधि है। आज जब दुनिया आधुनिक तकनीक और
कुत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुकी है, तब भी नरिंगम
सेवो का आवश्यकता और महत्ता कम नहीं हुई। बल्कि और
अधिक बढ़ी है। मशीनों और का परिष्करण कर सकती है।

देशों में बेहतर वतन और सुविधाओं के कारण विकासशील देशों को अनेक प्रगतिशीलता नये विदेशों की ओर आकर्षित हो रही है। परिणामस्वरूप गरीब और विकासशील देशों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। विश्व स्तर पर नर्सों की बढ़ती आवश्यकता एवं संकेत देते हैं कि अगर वही समय में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता नर्सों की उपलब्धता और क्षमता पर ही निर्भर करेगी इसलिए यह समय नर्सों को केवल सेवक के रूप में देखना नहीं, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्णायक स्तर के रूप में स्वीकार करने का है। भारत जैसे विशाल देश में नर्सिंग सेना को अधिक सशक्त, सम्मानजनक और सुरक्षित बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। नर्सों के लिए बेहतर वेतनमान, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, पालन-अवकाश, मानसिक स्वास्थ्य सहाय्य, कौशल विकास और नेतृत्व के अवसर सुनिश्चित किये जाने चाहिए। निर्जी और सेतुल अस्पतालों को मिलकर ऐसा वातावरण

वैश्विक चुनौतियों, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति शृंखला की अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं। 15 मई से 20 मई तक प्रस्तावित उनकी बहुराष्ट्रीय विदेश यात्रा के दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति, आर्थिक हितों और सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस दौरान ऊर्जा सहयोग, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, रक्षा, निवेश, नवाचार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है।

वैश्विक संकट के बीच सबसे बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं मोदी

(नीरज कुमार दुबे)

भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों के साथ केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को भी विस्तार देना चाहता है।

वैश्विक चुनौतियों, बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, ऊर्जा संकट, आपूर्ति श्रृंखला की अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बड़े कूटनीतिक मिशन पर निकल रहे हैं। 15 मई से 20 मई तक प्रस्तावित अंतराष्ट्रीय विश्वेश यात्रा के दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात, नैदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। यह यात्रा भारत की वैश्विक रणनीति, आर्थिक हितों और सामरिक साझेदारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रही है। इस दौरान ऊर्जा सहयोग, व्यापार, हरित प्रौद्योगिकी, शिक्षा, निवेश, नवाचार और वैश्विक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका और अधिक मजबूत होने की संभावना है। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारत अपने पारंपरिक मित्र देशों के साथ केवल व्यापारिक संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमान, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग को भी विस्तार देना चाहता है। हाल के वर्षों में भारत ने विश्व मंच पर एक भारोसेमंद और संतुलित शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यही कारण है कि यूरोप और पश्चिम एशिया के देश भारत को भविष्य के आर्थिक और सामरिक साझेदार के रूप में देख रहे हैं।

हम आपका बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात से करेंगे, जहां वह राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग, निवेश, डिजिटल भुगतान,

क्षा और भारतीय समुदाय के कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा बीते पच्चीस वर्षों में भारत में निवेश करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते ने व्यापार को नई गति दी है। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त अरब अमीरात भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। इसके अलावा भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा दोनों देशों की सामरिक निकटता को और अधिक मजबूत बना रहा है। वहां रह रहे लाखों भारतीय दोनों देशों के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की मजबूत कड़ी है।

संयुक्त अरब
अमीरात के बाद
अमीरात नौदरलैंड जाणै। यह यात्रा भारत और नौदरलैंड के बीच बढ़ते आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा देणै। प्रधानमंत्री वहां के राजा विलेम अलेक्जेंडर, महारानी माक्सिम और प्रधानमंत्री रोब येटन से मुलाकात करें। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, रेलवे हाइड्रोजन, जल प्रबंधन, सीमांकडर और नवाचार जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ रहै। नौदरलैंड यूरोप में भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और भारत में कई निवेशकों में शामिल है। जल प्रबंधन और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नौदरलैंड की विशेषज्ञता भारत के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जातै। दोनों देश मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में भी एक समान दृष्टिकोण रखते हैं।

मोदी की स्वीडन की यात्रा भारत और नॉर्डिक देशों के साथ बढ़ते सहयोग को और मजबूत बनाएगी। प्रधानमंत्री गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उर्फ क्रिस्टर्नस से बात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, हरित परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, अंतरिक्ष और जलवायु कार्यवाही जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावनाएँ हैं। हमारे आपकी बता दें कि स्वीडन की अनेक प्रमुख कंपनियाँ भारत में सक्रिय हैं और दोनों देशों के बीच नवाचार आधारित साझेदारी तेजी से विकसित हो रही है। भारत और स्वीडन लोकतांत्रिक मूल्यों, सतत विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में समान सोच रखते हैं। हरित औद्योगिक परिवर्तन और जलवायु संरक्षण के लिए दोनों देशों का सहयोग वैश्व स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद नौवें जाएंगे, जहां वह तीसरे प्रधानमंत्री भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किस्म का शिखर सम्मेलन प्रथममंत्री की नौवें की पहली यात्रा होगी और पिछले १०० तैतालीस वर्षों में भारत से वहां होने वाली पहली प्रधानमंत्री। स्त्रीय यात्रा भी मानी जा रही है। नौवें के प्रधानमंत्री योनास गाल्ट स्टोर के साथ होने वाली वाता में व्यापार, निवेश, हरित विकास प्रौद्योगिकी और समुद्री अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर रहेगा। भारत और नौवें के संबंध समुद्री सहयोग, हरित ऊर्जा और समुद्री सत विकास पर आधारित है। भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के बाद दोनों देशों के विशाल संबंधों को नई यात्रा में मिलने की संभावना है। नौवें का आर्थिक पेंशन को भारतीय

पूजी बाजार में महत्वपूर्ण निवेश कर चुका है। अर्थात् वैश्व क्षेत्र हरित जगजगानी और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में दोनों देशों का सहयोग धार्मिक की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष होगा। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह चरण भारत और नॉर्डिक देशों के बीच प्रौद्योगिकी, नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, सतत विकास और समुद्री अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सहयोग का नई रणनीति दिशा देगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलेनी और राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के साथ उनकी बैठकें भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगी। दोनों देश 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इटली ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से अलग होकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारों को समर्थन दिया है, जिससे दोनों देशों की सामरिक निकटता बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में सह-विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर जोर दिया जा रहा है। इटली भारत के संयुक्त राख सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रयासों का भी समर्थन करता रहा है। वहां रह रहा भारतीय समुदाय दोनों देशों के संबंधों को सामाजिक और सांस्कृतिक मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह विदेश यात्रा केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बजटरी वैश्विक भूमिका का प्रतीक भी है। यह यात्रा भारत को ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सहयोग, हरित विकास, रक्षा साझेदारी और वैश्विक व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगी। साथ ही यह संदेश भी देगी कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत विश्व रणनीति और अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख और विश्वसनीय केंद्र बनकर उभर रहा है।

संक्षिप्त समाचार

अमेरिकी सीनेट में डि एगो गार्सिया सैन्य अड्डे का मुद्दा उठा

वाशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई के दौरान रणनीतिक रूप से अहम डि एगो गार्सिया सैन्य अड्डे का मुद्दा अचानक उठाया गया। रिपब्लिकन सांसद जॉन कैनेडी ने चेतावनी दी कि चागोस द्वीप समूह विवाद के जरिये हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। यह सुनवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट प्रस्ताव पर हुई। कैनेडी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर की चागोस द्वीप और मॉरीशस से जुड़ी योजनाओं की आलोचना की। कैनेडी ने कहा कि मॉरीशस के चीन से करीब संबंध हैं और यदि द्वीपों का नियंत्रण उसे मिलता तो यह अमेरिकी हितों के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मॉरीशस डि एगो गार्सिया की एक अतिरिक्त चाबी चीन को दे सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सीधे इस टिप्पणी का समर्थन नहीं किया। लेकिन उन्होंने डि एगो गार्सिया की रणनीतिक अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डि एगो गार्सिया अमेरिका के लिए बेहद अहम सैन्य स्थान है और भविष्य में भी वहां संचालन क्षमता बनाए रखना जरूरी है।

कोलंबिया में पिछले साल का सशस्त्र संघर्ष एक दशक में सबसे गंभीर: रेड क्रॉस रिपोर्ट

कोलंबिया, एंजेंसी। पिछले एक वर्ष में आम नागरिकों पर सशस्त्र संघर्ष का असर पिछले एक दशक में सबसे खराब रहा है। रेड क्रॉस की एक वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में विस्थापित लोगों की संख्या दोगुनी होकर 2,35,000 तक पहुंच गई, क्योंकि आपराधिक गिरोह और विद्रोही समूह सरकार और एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। छोटे शहरों और गांवों में विद्रोही समूहों की ओर से लगाए गए लॉकडाउन की घटनाएं भी 99 फीसदी बढ़ गई। पश्चात से कोलंबिया में विद्रोही समूह और ड्रग तस्कर ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण के लिए सरकार से लड़ते रहे हैं। 2016 के शांति समझौते के बाद हिंसा में कमी आई थी। लेकिन बाद में छोटे समूहों ने खाली हुए इलाकों पर कब्जा कर लिया। रेड क्रॉस ने कहा कि 2025 की स्थिति पिछले कई वर्षों से चले आ रहे लगातार बिगड़ते हालात का नतीजा है।

हंगरी में 16 साल बाद नई सरकार, मंत्रियों ने संभाले पदभार

बुडापेस्ट, एंजेंसी। यूरोपीय देश हंगरी में 16 साल के बाद व्यवस्था बदल गई है। मंत्रियों ने पदभार संभाल लिए हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में मंगलवार को प्रधानमंत्री पीटर मैयरार के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। सत्ता हस्तांतरण से पहले मैर्यार की प्रो-यूरोपीय तिरंगा पार्टी ने पिछले महीने ओर्बन की फिडेज पार्टी को हराकर दो-तिहाई बहुमत हासिल किया। इसी के साथ 16 साल से चला आ रहा ओर्बन के राजनीतिक सिस्टम का पटाक्षेप हो गया है। पीटर मैर्यार ने अपनी नीतियों का संकेत देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली नई सरकार सभी हंगरीवासियों की होगी और मंत्री राष्ट्र सेवा की भावना के साथ काम करेंगे। मैर्यार ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, सार्वजनिक धन की वसूली, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहाल करने जैसे लुभावने वादे भी किए। नई सरकार में 16 मंत्रालय हैं, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा के लिए अलग विभाग हैं। इसका लक्ष्य यूरोपीय संध के जमे हुए करीब 17 अरब यूरो के फंड को वापस लाना है, जिस पर विदेश मंत्री अनीता ओर्बन ने भी जोर दिया।

नेपाल में रखी गई स्कूल भवन की आधारशिला

काठमांडू, एंजेंसी। नेपाल के अछाम जिले में मंगलवार को भारत की सहायता से एक स्कूल भवन की आधारशिला रखी गई। यह बसुकी माध्यमिक विद्यालय सुदूरपश्चिम प्रांत में बन रहा है। भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव नारायण सिंह और मेलेख ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष ज्वाला सिंह सऊद ने आधारशिला रखी। भारत सरकार 38 दस लाख नेपाली रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यह उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना का हिस्सा है। अध्यक्ष सऊद ने भारत के विकास समर्थन की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह छात्रों के सीखने के माहौल को बेहतर बनाएगा।

पश्चिम एशिया संकट: ईरान ने अमेरिका को दी परमाणु हथियारों की धमकी

दुबई/वाशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिका की तरफ से शांति प्रस्ताव पर ईरानी के जवाब को खारिज किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। ईरान ने जहां दोबारा हमला करने पर हथियार बनाने के स्तर पर यूरेनियम के संवर्धन की चेतावनी दी है, वहीं बताया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ फिर से व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

ईरान के संसदीय प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने मंगलवार को अमेरिका को खुले तौर पर परमाणु हथियारों की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनके देश पर दोबारा हमला होता है तो तेहरान 90 प्रतिशत शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन कर सकता है। इसे हथियार बनाने लायक माना जाता है। संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता रेजाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक और हमलों की स्थिति में ईरान के पास उपलब्ध विकल्पों

ट्रंप के रक्षा बजट पर बवाल: ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद में घमासान, हेगसेथ बोले- अब भी हमारे हाथ में सारे पते

वाशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा कि तमाम तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी संकट के बावजूद अमेरिका अब भी सभी पते अपने हाथ में रखता है।

सीनेट विनियोग उपसमिति के समक्ष रक्षा मामलों की सुनवाई के दौरान हेगसेथ ने डेमोक्रेट सांसदों के साथ तीखी बहस की। इस बैठक में जॉइंट चीफ्स चेयरमैन डैन केन भी मौजूद थे। सुनवाई का मुख्य मुद्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट, ईरान युद्ध की बढ़ती लागत, होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से बढ़ती तेल कीमतें और चीन-यूक्रेन को लेकर अमेरिकी रणनीति रही।

हेगसेथ ने ईरान को लेकर **क्या कहा?** हेगसेथ ने कहा कि ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने दावा किया कि 47 वर्षों से ईरान अमेरिका पर हमला करता रहा है और परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर झूठ बोलता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार कार्रवाई करने का साहस

दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की पूरी पारंपरिक नौसेना अब फारस की खाड़ी के तल में पड़ी है



और मौजूदा स्थिति में अमेरिका के पास पहले से ज्यादा दबदबा है। **हेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल:** हालांकि डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर झूठ बोलता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार कार्रवाई करने का साहस

हार्ट के लिए पांच सुपरफूड्स: अपने हृदय को रखें मजबूत रितिका समदर द्वारा

आज की तेज़-रफ्तार ज़िंदगी में खराब जीवनशैली और प्रोसेस्ड फूड्स पर बढ़ती निर्भरता के कारण उच्च कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य हृदय संबंधी समस्याएँ आम होती जा रही हैं। हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने की शुरुआत सही पोषण से होती है, और बादाम, फैटी फिश, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दालें तथा फल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करना महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है। मैक्स हेल्थकेयर में रीजनल हेड – डायटेटिक्स, रितिका समदर ने कुछ ऐसे हृदय-हितैषी खाद्य पदार्थों के बारे में बताया है, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और लंबे समय तक शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।

कैलिफोर्निया बादाम: रोज़ाना की डाइट में एक मुट्ठी बादाम शामिल करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर और एक हेल्दी सुपरफूड है। बादाम में विटामिन क्ष, मैग्नीशियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, ज़िंक सहित 15 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। हेल्दी डाइट के साथ कैलिफोर्निया बादाम का सेवन कुल और स्ट्रुकोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है तथा हृदय को नुकसान पहुंचाने वाली सूजन को भी घटा सकता है। जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन * में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, प्रतिदिन 42 ग्राम बादाम का सेवन करने से हृदय रोग के कई जोखिम कारकों में सुधार देखा गया, साथ ही HDL कोलेस्ट्रॉल में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

मछली: रोज़ाना या साप्ताहिक आहार में फैटी फिश को शामिल करना हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है, क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मीडिया पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान को झूठी उम्मीद देने और मदद करने का आरोप लगाया

वाशिंगटन डीसी, एंजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ खबरों में ऐसा दिखाया जा रहा है कि ईरान युद्ध में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ट्रंप ने फिर दावा किया कि ईरानी सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी है। ईरान के नेता खत्म हो चुके हैं और देश आर्थिक संकट में है।

ट्रंप ने यह बयान ट्रथ सोशल के जरिये दिया। उन्होंने मीडिया पर ईरान को 'झूठी उम्मीद' देने और उसकी 'मदद करने' का आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, जब फेक न्यूज में कहा जाता है कि ईरान सैन्य रूप से हमारे खिलाफ अच्छा कर रहा है, तो यह लगभग देशद्रोह जैसा है, क्योंकि यह पूरी तरह झूठ और बेतुकी बात है। वे दुश्मन की मदद कर रहे हैं। इससे ईरान को सिर्फ झूठी उम्मीद मिलती है। जबकि ऐसी कोई उम्मीद होनी ही नहीं चाहिए। ये अमेरिकी कायर हैं, जो अपने ही देश के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने दावा किया, ईरान की नौसेना के पास 159 जहाज थे और अब सभी समुद्र में डूब चुके हैं। उन्होंने कहा, ईरान के पास अब नौसेना नहीं है। उसकी वायुसेना खत्म हो चुकी है। उसकी तकनीक खत्म हो

चुकी है। उसके नेता अब नहीं रहे और देश आर्थिक तबाही का सामना कर रहा है। सिर्फ हारने वाले,



एहसान न मानने वाले और मूर्ख लोग ही अमेरिका के खिलाफ बोल सकते हैं। यह पोस्ट ऐसे समय आई है, जब ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अहम मुलाकात होने जा रही है।

इससे पहले चीन रवाना होने से पहले ट्रंप ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने फिर दावा किया कि ईरानी सेना पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और अमेरिका यह युद्ध 'शांति से या किसी भी तरीके से'

लक्ष्य और अंत की योजना के लड़ा जा रहा है, जिसकी कीमत अमेरिकी जनता चुका रही है। वहीं सीनेटर पैटी मरे ने बढ़ती ईंधन और खाद्य कीमतों के बीच भारी रक्षा खर्च पर सवाल उठाए।

ईरान युद्ध में अमेरिका का कितना हुआ खर्च?

पेंटागन के मुताबिक ईरान संघर्ष पर अब तक करीब 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, हालांकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है।

किन-किन विषयों पर हुई चर्चा?

सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल होर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने को लेकर उठा। वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम इस समुद्री मार्ग में व्यवधान के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इस पर हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों जापान, ताइवान और फिलीपींस के साथ साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आईडीएमसी रिपोर्ट में खुलासा: युद्ध और हिंसा ने दुनिया में मचाई तबाही, अपने ही देश में बेघर हुए 8.2 करोड़ लोग

जिनेवा, एंजेंसी। दुनियाभर में संघर्ष, गृहयुद्ध, सांप्रदायिक हिंसा और जलवायु आपदाओं ने करोड़ों लोगों को अपने ही देश में बेघर कर दिया है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर (आईडीएमसी) व नॉर्वेजियन रिफ्यूजी कार्ड्सिल (एनआरसी) की ताजा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2026 के अनुसार 2025 के अंत तक 104 देशों में 8 करोड़ 22 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित जीवन जी रहे थे। यह संख्या जर्मनी की आबादी के बराबर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों में यह आंकड़ा दोगुने से अधिक हो गया है और पहली बार युद्ध तथा हिंसा ने प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 करोड़ 22 लाख विस्थापितों में 6 करोड़ 86 लाख लोग संघर्ष और हिंसा के कारण बेघर हुए।

रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 में इस्राइल और ईरान के बीच हुए 12 दिन के संघर्ष ने आधुनिक समय की सबसे बड़ी एकल आंतरिक विस्थापन घटना पैदा की। इस्राइली सैन्य कार्रवाई और निकासी चेतावनियों के बाद तेहरान से करीब एक

बंद करे। जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी माना कि ईरान अपनी सैन्य गतिविधियों के जरिए दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने सैन्य योजनाओं पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। सुनवाई में मिच मैककोनेल ने नाटो सहयोगियों और यूक्रेन को समर्थन जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे समय में जब अमेरिका के विरोधी देश एकजुट हो रहे हैं, सहयोगियों से दूरी बनाना खतरनाक हो सकता है।

ट्रंप की चीन यात्रा पर हुई चर्चा

वहीं चीन को लेकर भी अमेरिका की रणनीति पर चर्चा हुई। ट्रंप की संभावित बीजिंग यात्रा से पहले मैककॉनेल ने पूछा कि क्या ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी प्रतिबद्धताएं कायम रहेंगी। इस पर हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों जापान, ताइवान और फिलीपींस के साथ साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ट्रंप के वक्तव्यों के बाद चीन ने कहा कि ट्रंप की संभावित यात्रा से पहले मैककॉनेल ने पूछा कि क्या ताइवान और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी प्रतिबद्धताएं कायम रहेंगी। इस पर हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों जापान, ताइवान और फिलीपींस के साथ साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।



आईडीएमसी के अनुसार इतने कम वक्त में एक देश में इतनी बड़ी आबादी के विस्थापन का यह अब तक का सबसे बड़ा मामला है। फलस्तीन में 2025 के दौरान 27 लाख 56 हजार बार विस्थापन दर्ज किया गया। वर्ष के अंत तक करीब 20 लाख लोग अब भी विस्थापित थे। गाजा में जनवरी के युद्धविराम के बाद लाखों लोग लौटे, लेकिन बुनियादी ढांचा तबाह होने के कारण हालात सामान्य नहीं हो सके। मार्च में फिर संघर्ष शुरू हो गया और

ईरानी हमलों का सऊदी ने दिया था करारा जवाब, कई इलाकों पर किए थे हवाई हमले; रिपोर्ट में खुलासा

रियाद, एंजेंसी। सऊदी अरब की वायुसेना ने मार्च के अंत ईरान पर कई गुप्त हमले किए। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में पश्चिम और ईरानी अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी समाने आई है। यह पहली बार है जब सऊदी अरब ने सीधे ईरान पर हमला किया है। इससे पता चलता है कि रियाद अब अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ज्यादा कड़ा रख अपना रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ये हमले सऊदी अरब पर हुए हमलों का बदला लेने के लिए किए गए थे। हालांकि इन हमलों में किन जगहों को निशाना बनाया गया, इसकी पुष्टि ना हो पाई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई सा जवाब नहीं दिया और ईरान की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया साम नहीं आई। इन हमलों से साफ है कि पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षे में संघर्ष काफी बढ़ गया है। तनाव को और ज्यादा बढ़ने से रोक के लिए सऊदी अरब लगातार ईरान के संपर्क में रहा। रिपोर्ट मुताबिक, सऊदी अरब ने ईरान को इन हमलों की जानकारी दी थी इसके बाद बड़े स्तर पर कूटनीतिक बातचीत हुई। सऊदी अरब चेतावनी दी थी कि अगर हमले नहीं रुके तो वह और कड़ी कार्रवा करेगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने को लेख एक अनौपचारिक समझौता हुआ। यह समझौता 7 अप्रैल व अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम से ठीक एक हफ्ते पछे लागू हुआ था। ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों देश दुश्म खत्म करने और आपसी हितों की रक्षा के लिए सहमत हुए हैं। मा के महीने में तनाव काफी बढ़ गया था। 19 मार्च को सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा था कि जरूरत पड़ने प उनका देश सैन्य कार्रवाई का अधिकार रखता है। इसके तीन दि बाद सऊदी अरब ने ईरान के सैन्य अताशे और चार दूतावास कर्मचारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया था।

आईडीएमसी रिपोर्ट में खुलासा: युद्ध और हिंसा ने दुनिया में मचाई तबाही, अपने ही देश में बेघर हुए 8.2 करोड़ लोग

अगस्त में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। पश्ि तट में भी 1967 के बाद सबसे बड़े पैमाने विस्थापन दर्ज हुआ। 36 लाख लोग बाढ़, भू-तुफान और अन्य आपदाओं की वजह से विस्था हुए। आईडीएमसी की निदेशक ट्रेसी लुकास ने ं कि संख्या में मामूली गिरावट के बावजूद सि अब भी रिकॉर्ड स्तर के बेहद करीब है और वास्तविक सुधार नहीं माना जा सकता। इंटर डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की 2026 वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में आंत रूप से विस्थापित लोगों की संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो गई है, जो जर्मनी की कुल आबादी बराबर है। पिछले एक दशक में यह आंकड़ा दो हो चुका है। रिपोर्ट में चौकाने वाला खुलासा हुआ कि पहली बार युद्ध और हिंसा, प्राकृतिक आपदा से बड़ा विस्थापन का कारण बने हैं। जून 202. इजरायल-ईरान संघर्ष के दौरान तेहरान से करोड़ों लोगों का पलायन आधुनिक इतिहास सबसे बड़ी विस्थापन घटना रही। इसके अला सूडान और फलस्तीन में भी हालात चिंताजनक हुए हैं।

ट्रंप से टकराव के कारण छिन्न-मार्टी मकरी की कुर्सी

वाशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक संस्था एफडीए के कमिश्नर डॉक्टर मार्टी मकरी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कार्यक समय से प्रशासन के भीतर और बाहर से उन पर दबाव बनाया जा रहा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रथ सोशल पर इसकी पुष्टि की। ट्रंप ने मकरी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक कठोर परिश्रमी डॉक्टर बताया। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ट्रंप उन्हें बर्खास्त करने की योजना को पहले ही मंजूरी दे चुके थे। अब उनकी जगह काइल डायमांट कार्यकारी प्रमुख की जिम्मेदारी संभालेंगे। डॉक्टर मकरी के इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ी वजह ई-सिगरेट नीति को माना जा रहा है। पिछले सप्ताह एफडीए ने पहली बार फ्लूट-पेलेवर्ड ई-सिगरेट को बाजार में उतारने की मंजूरी दी थी। मकरी इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था फलों के स्वाद वाले वेपस बच्चों और युवाओं को नशे की लत में धकेल दें न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, इसी वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। प्रशासन के अन्य अधिकारी इस मंजूरी के पक्ष थे, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। मकरी का एक साल का कार्यकाल सिवावो से घिरा रहा। उनके नेतृत्व में एफडीए के भीतर भारी अस्थिरता देखी गई। एंजेंसी के लगभग सभी वरिष्ठ करियर अधिकारि या तो इस्तीफा दिया या उन्हें हटा दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर के हस्तक्षेप और राजनीतिक हितों के कारण वैज्ञानिक सिद्धांतों से समझौते के आरोप लगे। ड्रग सेंटर में एक साल के भीतर छह अलग-अलग निदेशक बदले गए। इससे कर्मचारियों का मनोबल गिर ग और एंजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। डॉक्टर मकरी को चोतरफा विरोध का सामना करना पड़ा। फार्मा कंपनियों के सीईओ उनव नीतियों से असंतुष्ट थे।

ब्रिटेन ने ईरानी संगठनों व व्यक्तियों पर लगाए नए प्रतिबंध

ब्रिटेन ने अपनी धरती पर शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में ईरानी संगठनों और व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया है। ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय (एफसीडीओ) ने कहा कि सोमवार को घोषित ये नए उपाय वैश्विक सुरक्षा के खिलाफ ईरानी कार्रवाई और विदेशों में धमकियां देने के लिए आपराधिक गिरोहों के इस्तेमाल के जवाब में उठाए गए हैं। जिन संस्थाओं को प्रतिबंध के दायरे में लाया गया उनमें बेरेलियन एक्सचेंज, जीसीएम एक्सचेंज और जिंदाशरी नेटवर्क शामिल हैं। प्रतिबंध सूची में शामिल व्यक्तियों में मंसूर जारिगहलम, नासिर जारिगहलम, एक्रमे अब्दुलकरीम ओस्टुनक, निहात अब्दुल कादिर असान रजा हामिदिरावरी और नामिक सालिफोव शामिल हैं। इसाइल में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी ने मंगलवार को कहा कि ईरान युद्ध के दौरान देश की रक्षा के लिए इसाइल ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को आयरन डोम मिसाइलरोधी बैटरियां और उन्हें संचालित करने के लिए कमी भेजे थे। तेल अवीव सम्मेलन में हकाबी ने कहा, मैं अब्राहम समझौते के पहले सदस्य यूएई की सराहना करना चाहूंगा। इसके लाभों को देखिए। इसाइल ने उनकी मदद के लिए आयरन डोम बैटरियां और उन्हें संचालित करने के लिए कमी भेजे हैं। यूएई ने वर्ष 2020 में कूटनीतिक रूप से इसाइल को मान्यता दी थी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध पर अब तक करीब 29 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

